साप्ताहिक
Live not just breaTHE

दि कार्मिक पोस्ट

MPHIN/2015/63220
MP/IDC1528/22-23

Earth provides enough to satisfy every man's needs, but not every...

Email- thekaarmiicpost@gmail.com

वर्ष : 11, अंक : 17 (प्रति बुधवार), इन्दौर, 26 नवंबर 2025 से 2 दिसंबर 2025 पेज : 8 कीमत : 3 रुपये

बातों, वादों पर जोर, उम्मीदों पर खरी नहीं रही कॉप-30 वार्ता: सीएसई

ब्राजील बेलेम में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन (कॉप-30) से दुनिया को बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन परिणाम उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे, इसके नतीजों ने दुनिया को निराश किया है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट की उस टीम का जो इस बैठक पर लगातार नजर बनाए हुए थी, उसका कहना है दुनिया को उम्मीद थी यह कॉप सच बोलने और कड़े कदम उठाने वाला मोड़ साबित होगी, लेकिन इस बार भी यह बैठक महज बातों और वादों की कॉप बनकर रह गई। इस दौरान जहां वार्ताओं का लम्बा दौर चला लेकिन नतीजों के नाम पर, कुछ संवाद, कुछ वादे और एक एक अस्पष्ट-सा तंत्रज्बस इतना ही सामने आया। 22 नवंबर को ब्राजील की कॉप-30 अध्यक्षता ने 'बेलेम पॉलिटिकल पैकेज' जारी किया। इसमें तीन मुख्य बातें शामिल की गई, पहला न्यायसंगत बदलाव (जस्ट ट्रांजिशन) के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग तंत्र, दूसरा अनुकूलन के लिए वित्त (एडाप्टेशन फाइनेंस) को 2035 तक तीन गुना बढ़ाने का वादा, और तीसरा पेरिस समझौते के अनुच्छेद 9 के तहत वित्त प्रवाह की जांच के लिए नए कार्यक्रम को मंजूरी।

लेकिन सबसे बड़ा सवाल बना रहा फॉसिल फ्यूल्स, क्योंकि इस पर कोई स्पष्ट निर्णय नहीं लिया गया। हालांकि इसके बदले ब्राजील ने औपचारिक प्रक्रिया के बाहर दो अलग रोडमैप प्रस्तुत किए। इसी तरह वन विनाश के मुद्दे पर भी चर्चाएं कॉप की औपचारिक प्रक्रिया के बाहर हुईं। सीएसई में क्लाइमेट प्रोग्राम टीम की मैनेजर अवंतिका गोस्वामी का कहना है, भले ही जस्ट ट्रांजिशन पर बना यह नया तंत्र, विकासशील देशों और समाज की जीत है, क्योंकि वे लोग लम्बे समय से इसकी मांग कर रहे थे। इसका उद्देश्य न्यायपूर्ण बदलाव के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग, तकनीकी मदद, ज्ञान साझा करने और क्षमता बढ़ाने को मजबूत करना है। लेकिन इसकी समयसीमा, तकनीकी भूमिका और अनुकूलन वित्त (एडाप्टेशन फाइनेंस) अब भी अस्पष्ट और कमजोर है। यह इस तंत्र की सफलता को लेकर सवाल खड़ा करता है।

जी77 और चीन समूह ने इस बार साफ तौर पर अपनी सामूहिक ताकत का प्रदर्शन किया और अपनी प्राथमिकताओं को केंद्र में रखा। लेकिन विकसित देशों ने बार-बार चर्चा को भटकाने की कोशिश की, जैसे बड़े विकासशील देशों पर 'महत्वाकांक्षा रोकने' का आरोप लगाना और विकासशील देशों को आपस में बांटने की कोशिशें करना। गोस्वामी का कहना है, इससे कॉप प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ है। अब यह साफ नहीं है कि यह प्रक्रिया किसके हित में काम कर रही है और क्या यह अपने उद्देश्य पर खरी भी उतर पा रही है। गोस्वामी के मुताबिक पेरिस समझौते ने जलवायु कार्रवाई की दिशा ही बदल दी। इस समझौते ने क्योटो प्रोटोकॉल की तरह देशों पर ऊपर से लक्ष्य थोपने के बजाय, स्वैच्छिक वादों पर जोर दिया और विकसित-विकासशील देशों के बीच का फर्क कम कर दिया। अब इस ढांचे की खामियां सामने आ रही हैं, इसके चलते विकसित देश तो जीवाश्म ईंधन का उत्पादन और इस्तेमाल जारी रखकर भी जवाबदेही से बच जाते हैं, जबकि दोष दक्षिण की तेजी से उभरती अर्थव्यवस्थाओं पर मढ़ दिया जाता है। गौरतलब है कि पेरिस समझौते में देशों को अपनी मर्जी से लक्ष्य तय करने की छूट दी गई है। विशेषज्ञों के मुताबिक ऐसे समय में जब चीन दुनिया का सबसे बड़ा स्वच्छ तकनीकी कार्यक्रम चला रहा है और भारत लगातार अक्षय ऊर्जा को बढ़ा रहा है, तब विकासशील देशों को 'रोड़ा' बताने की यह कहानी झूठी और बांटने वाली लगती है। ऐसी बंटी और टकराव भरी स्थिति में सहमति और सहयोग की गुंजाइश बहुत कम रह जाती है, जबकि हमारी तेजी से गर्म होती दुनिया को इनकी सबसे ज्यादा जरूरत है। देखा जाए तो इस समय विकसित देशों को अपनी वित्तीय जिम्मेदारियां निभाकर मौजूदा राष्ट्रीय जलवायु प्रतिबद्धताओं (एनडीसी) को लागू करने में मदद करनी चाहिए थी। लेकिन इसके बजाय, विकसित देश खुद को 'क्लाइमेट लीडर' दिखाने में लगे रहे, जबकि उनके अपने खुद के एनडीसी बेहद कमजोर हैं। इसके साथ ही बातचीत में अब भी विकसित देशों और उनकी मीडिया की सामूहिक ताकत हावी दिखाई देती है। वैश्विक अनुकूलन लक्ष्य के लिए संकेतकों की सूची तो अपनाई गई है, लेकिन निर्णय पर गंभीर चिंताएं बनी हुई हैं। लेकिन उन्हें लागू करने और प्रभावी बनाने के लिए वित्त और साधन तय नहीं किए गए। साथ ही क्रियान्वयन के उपायों की भी कमी है। वार्ता में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव बहुत देर से पेश किए गए, जिससे उनकी समीक्षा या चर्चा का समय कम रह गया। देखा जाए तो कागजों पर यह ढांचा तो आगे बढ़ा है, लेकिन धरातल पर कमजोर दिख रहा है।

यदि विकासशील देशों के लिए उन्हें लागू करने के उपाय नहीं हैं, तो वैश्विक अनुकूलन लक्ष्य केवल उम्मीदें तय करता है, लेकिन उन्हें पूरा करने का तरीका नहीं देता। अनुकूलन वित्त को 2035 तक तीन गुणा करने की घोषणा भी कमजोर मानी गई क्योंकि इसमें यह स्पष्ट नहीं कि पैसा कौन देगा और किस आधार पर लिया जाएगा। विकासशील देशों ने कॉप-29 की वित्तीय विफलता को सुधारने का लक्ष्य लेकर कॉप-30 में प्रवेश किया। लेकिन उनकी प्रमुख मांगें, जैसे सार्वजनिक वित्त की जवाबदेही तय करना बार-बार रोकी गईं। उनका प्रयास, अनुच्छेद 9.1 को एजेंडे में शामिल कराने का, विफल रहा। इसके बजाय, उन्हें अनुच्छेद 9 पर दो साल का कमजोर कार्य कार्यक्रम सौंपा गया, जिसमें एक नोट शामिल है जो इसे कॉप 29 में अपनाए गए नए सामूहिक वित्त लक्ष्य से अलग कर देता है। जवाबदेही को एक और झटका तब लगा।

ध्रुवीय क्षेत्रों में बदलती जलवायु का दुनिया भर में स्वास्थ्य पर पड़ रहा है गहरा असर– शोध

न्यूयार्क। यूनिवर्सिटी ऑफ एग्जेटर के शोधकर्ताओं के द्वारा किए गए अध्ययन ने दिखाया है कि ध्रुवीय क्षेत्रों में हो रहे बदलाव केवल स्थानीय समस्या नहीं हैं, बल्कि उनका असर पूरी दुनिया के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। ध्रुवीय इलाके पृथ्वी के सबसे तेजी से गर्म हो रहे हिस्सों में शामिल हैं। वहां बर्फ पिघल रही है, समुद्र का स्तर बढ़ रहा है और मौसम पैटर्न बदल रहे हैं। ये बदलाव सीधे और अप्रत्यक्ष रूप से मानव स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव डाल सकते हैं। शोध में पाया गया है कि वर्तमान मॉडल इन प्रभावों का सही आकलन नहीं कर रहे हैं। इससे पुरानी बीमारियों, मानसिक स्वास्थ्य की समस्याओं और गर्भावस्था संबंधित जटिलताओं का खतरा बढ़ सकता है। एम्बियो नामक पत्रिका में प्रकाशित शोध पत्र में शोधकर्ता के हवाले से कहा गया है कि ध्रुवीय बदलाव कोई दूर का संकट नहीं है। बर्फ के पिघलने, समुद्र स्तर बढ़ने और मौसम बदलने के जटिल प्रभाव पूरी दुनिया में भोजन सुरक्षा, बीमारियों और स्वास्थ्य ढांचे को प्रभावित कर रहे हैं। यह केवल पर्यावरणीय समस्या नहीं, बल्कि एक वैश्विक स्वास्थ्य आपात स्थिति है। ध्रुवीय क्षेत्रों के गर्म होने से कई प्रकार की फीडबैक लूप और टपिंग पॉइंट बन रहे हैं। उदाहरण के लिए, बढ़ते तापमान से जेट स्ट्रीम कमजोर हो रही है और महासागरीय धाराएं बदल रही हैं। इसका सीधा असर मौसम पर पड़ता है, जिससे अधिक संख्या में आपदाएं और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां बढ़ रही हैं। इसके अलावा आर्कटिक में बर्फ के बिना रहने वाली परिस्थितियां एल नीनो जैसी घटनाओं की तीव्रता बढ़ा सकती हैं। तापमान वृद्धि के कारण किडनी और हृदय संबंधी रोगों में वृद्धि होने की आशंका है। समुद्र स्तर बढ़ने से भूजल में खारा पानी मिल सकता है, जिससे प्रीक्लेम्पसिया, शिशु मृत्यु और कुछ प्रकार के कैंसर बढ़ सकते हैं। ध्रुवीय इलाकों में बदलाव का असर सीधे कृषि पर भी पड़ रहा है। बारिश और तापमान के पैटर्न बदलने से फसल उत्पादन प्रभावित हो रहा है, जिससे कुपोषण और उससे जुड़ी बीमारियां बढ़ सकती हैं। यह समस्या खासकर उन देशों में गंभीर हो सकती है, जो पहले से ही पोषण और स्वास्थ्य के मामलों में संवेदनशील हैं। गर्म होने वाले जलवायु के कारण कीट और जानवरों से फैलने वाली बीमारियां, जैसे कि डेंगू, लाइम रोग और वाइब्रोसिस, उन क्षेत्रों में फैल रही हैं जो पहले इन रोगों से अछूते थे। बाढ़ की घटनाओं में वृद्धि से जलजनित रोग, जैसे कॉलरा और टाइफाइड, फैल रहे हैं। आर्कटिक में पर्माफ्रॉस्ट और समुद्र की बर्फ पिघलने से बुनियादी ढांचे को खतरा है। साथ ही, पुराने प्रदूषक और प्राचीन रोगजनक जैसे 1918 के इन्फ्लूएंजा वायरस के निकलने का खतरा भी बढ़ रहा है। महासागरीय पारिस्थितिकी तंत्र में बदलाव से पारंपरिक खाद्य स्रोतों पर असर पड़ रहा है, जिससे स्थानीय समुदायों में कुपोषण, गर्भपात, किडनी और हृदय रोगों की दर बढ़ रही है। शोध में यह स्पष्ट किया गया है कि ध्रुवीय बदलाव के स्वास्थ्य पर प्रभाव को स्वास्थ्य योजना और नीति में शामिल करना आवश्यक है। शोध में कहा गया है कि बीमारियों और मृत्यु के इन कारणों की अनदेखी नहीं की जा सकती। इसके लिए जलवायु वैज्ञानिकों, स्वास्थ्य विशेषज्ञों और आंकड़े विशेषज्ञों के बीच मजबूत अंतरराष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता है ताकि हम भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार हो सकें ।

श्रीलंका में म.प्र. पर्यटन प्रतिनिधिमंडल ने बौद्ध सर्किट को दिया नया आयाम

प्रदेश के बौद्ध स्थलों को प्रचारित करने का किया आग्रह

स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र में आयोजित विशेष सभा में लिया भाग

पर्यटन मंत्री श्री विजित हेराथ और श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त श्री संतोष झा से की महत्वपूर्ण चर्चा

रामायण की कथाओं को जीवंत करने वाले कलाकारों व कहानीकारों के साथ प्रदेश के बौद्ध स्थलों को प्रचारित करने का आग्रह भी किया।

भोपाल भारत और श्रीलंका के मध्य अनादि काल से चली आ रही सांस्कृतिक और आध्यात्मिक साझेदारी को और सुदृढ़ करने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश पर्यटन का एक उच्च-स्तरीय प्रतिनिधिमंडल इन दिनों श्रीलंका की सद्भावना यात्रा पर है। यह यात्रा, कोलंबो स्थित भारतीय उच्चायोग के आमंत्रण पर आयोजित की गई है। म.प्र. राज्य पर्यटन विकास निगम के प्रबंध निदेशक, डॉ. इलैयाराजा टी. के नेतृत्व में उप सचिव पर्यटन श्री राजेश गुप्ता और ज्वाइंट डायरेक्टर टूरिज्म बोर्ड डॉ. एस. के. श्रीवास्तव ने श्रीलंका में मध्यप्रदेश के बौद्ध सर्किट का प्रचार किया और साथ ही कोलंबो में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों के दौरान, प्रतिनिधिमंडल ने वहाँ की अग्रणी हॉस्पिटैलिटी कंपनियों से भेंट की। इन सार्थक वार्ताओं में, मध्यप्रदेश के विशाल पर्यटन सामर्थ्य—जिसमें समृद्ध संस्कृति, प्राचीन धरोहर, वन्यजीवों की अनुपम छटा, रोमांचक गतिविधियाँ, और आध्यात्मिक व कल्याणकारी पर्यटन के अवसर समाहित हैं—को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया गया। इस यात्रा का एक महत्त्वपूर्ण पड़ाव श्रीलंका के विदेश मामले, विदेशी रोज़गार और पर्यटन मंत्री श्री विजित हेराथ के साथ हुई बैठक थी। डॉ. इलैयाराजा टी. ने अपने सारगर्भित प्रस्तुतीकरण में दोनों राष्ट्रों के गहरे सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंधों की नींव को रेखांकित किया। मंत्री श्री हेराथ ने द्विपक्षीय पर्यटन को बढ़ाने के लिए विस्तृत संभावनाओं पर बल दिया और सहयोग को और मज़बूत करने की अपनी उत्कट इच्छा व्यक्त की। इस अवसर पर, श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त महामहिम श्री संतोष झा ने पर्यटन और आतिथ्य सत्कार के क्षेत्र में सहयोग के नवीन मार्गों पर प्रकाश डाला, जबकि भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय के संयुक्त सचिव श्री हरिकिशोर एस. ने कनेक्टिविटी और पर्यटक अनुभव को उत्कृष्ट बनाने की दिशा में चल रही पहलों का विवरण दिया। प्रतिनिधिमंडल ने स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र में आयोजित एक विशेष सभा में भाग लिया, जिसकी अध्यक्षता श्री लंका महाबोधि सोसाइटी के अध्यक्ष श्री बनागला उपतिस्स नायक थेरो ने की थी। उन्होंने अपने उद्बोधन में भारत और श्रीलंका के मध्य विद्यमान अविभाज्य सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और पारंपरिक बंधनों को बड़े स्नेह से समझाया।

पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिलाने के लिए आवश्यक पहल की जाए -मुख्यमंत्री डॉ. यादव

प्रदेश में हेल्थ और वेलनेस टूरिज्म को करें प्रोत्साहित

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड के संचालन की 8वीं बैठक

भोपाल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिलाने के लिए आवश्यक पहल की जाए। इससे नवाचार के इच्छुक व्यक्तियों तथा उद्यमियों को सुविधाएं उपलब्ध होंगी, जिससे प्रदेश के विभिन्न अंचलों में पर्यटन गतिविधियों के संचालन और सुविधाओं के विस्तार में आसानी होगी।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में हेल्थ और वेलनेस टूरिज्म को बढ़ावा देने की पर्याप्त संभावनाएं हैं। अतः पर्यटन विभाग, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा तथा आयुष विभाग के साथ मिलकर परस्पर समन्वय से गतिविधियां संचालित करें। जिन राज्यों में ऐसी गतिविधियां संचालित हैं, उनका अध्ययन कर प्रदेश में संभागवार कार्ययोजना बनाई जाए। वेलनेस टूरिज्म को प्रोत्साहित करने में धार्मिक संस्थाओं और ट्रस्टों का भी सहयोग लिया जा सकता है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रदेश के इतिहास और संस्कृति पर केन्द्रित तथा उनसे संबंधित फिल्मों के निर्माण को प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वैश्विक स्तर पर संचालित वन्य जीवों और वनों पर केन्द्रित टीवी चैनल्स पर मध्यप्रदेश के समृद्ध वनों और जैवसंपदा के प्रस्तुतिकरण के लिए भी प्रयास किए जाएं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मंगलवार को मध्यप्रदेश टूरिज्म मंडल के संचालक मंडल की मंत्रालय में हुई 8वीं बैठक में यह निर्देश दिए। बैठक में संस्कृति, पर्यटन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री धर्मेन्द्र भाव सिंह लोधी, मुख्य सचिव श्री अनुराग जैन सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में पीएमश्री पर्यटन हेलीकॉप्टर सेवा के अंतर्गत इंदौर-उज्जैन-ओंकारेश्वर सेक्टर, भोपाल-मढ़ई-पचमढ़ी सेक्टर और जबलपुर-बांधवागढ़-कान्हा सेक्टर में सेवा संचालन के संबंध में चर्चा हुई। साथ ही सिंहस्थ-2028 के लिए जारी गतिविधियों, ग्रामीण पर्यटन को प्रोत्साहन करने के लिए संचालित योजनाओं, साहसिक पर्यटन, जल पर्यटन गतिविधियों, पर्यटन क्षेत्र में निवेश संवर्धन और मध्यप्रदेश पर्यटन के राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचार-प्रसार के संबंध में भी पर चर्चा हुई।

टूरिस्ट हेली सर्विस का उठाएं भरपूर लाभ - मुख्यमंत्री डॉ. यादव

सालभर में 13.41 करोड़ से अधिक पर्यटक मध्यप्रदेश आए

भोपाल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि विश्व धरोहर स्थल खजुराहो और पन्ना टाइगर रिजर्व के आसपास पर्यटकों के लिए सभी प्रकार की सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। खजुराहो में एयरपोर्ट तो पहले से है ही, अब प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने वाराणसी से खजुराहो नई वंदे भारत ट्रेन की सौगात दे दी है, जिससे बुंदेलखंड की शान मतंगेश्वर महादेव सीधे काशी विश्वनाथ से जुड़ गए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने पर्यटकों की सुविधाओं में बढ़ोतरी करते हुए नई पीएमश्री हेली टूरिस्ट सर्विस शुरू की है। इसके अलावा प्रदेशवासियों को इंटर स्टेट हवाई सेवा और एयर एंबुलेंस की सुविधा भी मिल रही है। पर्यटक इन सुविधाओं का भरपूर लाभ उठाएं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश आने वाले पर्यटकों की संख्या में 526 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है। बीते साल 13 करोड़ 41 लाख से अधिक पर्यटक मध्यप्रदेश की धरती पर आए। हमारी पर्यटन प्रोत्साहन योजनाओं के कारण भविष्य में यह आंकड़ा और भी बढ़ेगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव बुधवार को खजुराहो में एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने खजुराहो में %होटल द ओबेरॉय राजगढ़ पैलेस% का दीप प्रज्ज्वलन एवं फीता काटकर विधिवत शुभारंभ किया। इस अवसर पर ओबेरॉय ग्रुप के स्वामी श्री अर्जुन ओबेरॉय ने पुष्पगुच्छ एवं शॉल ओढाकर मुख्यमंत्री डॉ. यादव का आत्मीय स्वागत एवं अभिनंदन किया।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि खजुराहो का ईश्वर का विशेष आशीर्वाद प्राप्त है। ओबेरॉय ग्रुप के राजगढ़ पैलेस होटल के माध्यम से आज खजुराहो समृद्धि के एक नए दौर में प्रवेश कर रहा है। राज्य सरकार बुंदेलखंड के विकास के लिए लगातार काम कर रही है। खजुराहो की प्राचीनतम स्थापत्य कला को देखने के लिए पूरी दुनिया खिंची चली आती है। खजुराहो महाराजा छत्रसाल की राजधानी रही है। बुंदेलखंड में आल्हा-ऊदल की वीरता की कहानियां जोश से भर देती हैं। यहां 70 एकड़ में यह भव्य होटल बनकर तैयार हुआ है, जिससे पर्यटकों को तो लग्जरियस फेसिलिटी मिलेगी ही, स्थानीय लोगों को भी रोजगार मिलेगा।

क्षेत्रीय सांसद श्री वीडी शर्मा ने कहा कि मध्यप्रदेश के लिए आज ऐतिहासिक दिन है। खजुराहो एक विश्व धरोहर है, यहां रोजाना दुनियाभर के पर्यटक आते हैं। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने भारत में 17 आइकोनिक सिटी चिह्नित की हैं, इनमें खजुराहो भी शामिल है। यहां नजदीक ही पन्ना टाइगर रिजर्व को देखने के लिए भी बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटक आते हैं। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने खजुराहो को हवाई सेवा के साथ सुपरफॉस्ट ट्रेन वंदे भारत की रेगुलर कनेक्टिविटी भी दे दी है। पन्ना में हीरे तो मिलते ही हैं, भविष्य में राजगढ़ पैलेस %होटल इंडस्ट्री का डायमंड% बनकर उभरेगा। राजगढ़ पैलेस की भव्यता की जानकारी देते हुए श्री अर्जुन ओबेरॉय ने बताया कि मध्यप्रदेश अतुलनीय पर्यटन संभावनाओं और संस्कृति का केंद्र है। राजगढ़ पैलेस के डिजाइन और रूप आगंतुकों को मध्यप्रदेश की ऐतिहासिक विरासत को करीब से देखने का मौका देगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि राजगढ़ पैलेस पर्यटकों के लिए मध्यप्रदेश का गेट-वे बनेगा। कार्यक्रम में वन एवं पर्यावरण राज्यमंत्री श्री दिलीप अहिरवार, विधायक श्री अरविंद पटेरिया, विधायक श्रीमती ललिता यादव, विधायक श्री राजेश शुक्ला, विधायक श्री कामाख्या प्रताप सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती विद्या अग्निहोत्री, अपर मुख्य सचिव संस्कृति एवं पर्यटन श्री शिव शेखर शुक्ला, डी आईजी विजय खत्री, कलेक्टर श्री पार्थ जैसवाल, पुलिस अधीक्षक श्री अगम जैन सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं ओबेरॉय ग्रुप के स्टॉफ मेंबर्स उपस्थित रहे।

दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण का कहर, गाजियाबाद में 434, दिल्ली में 370 एक्यूआई

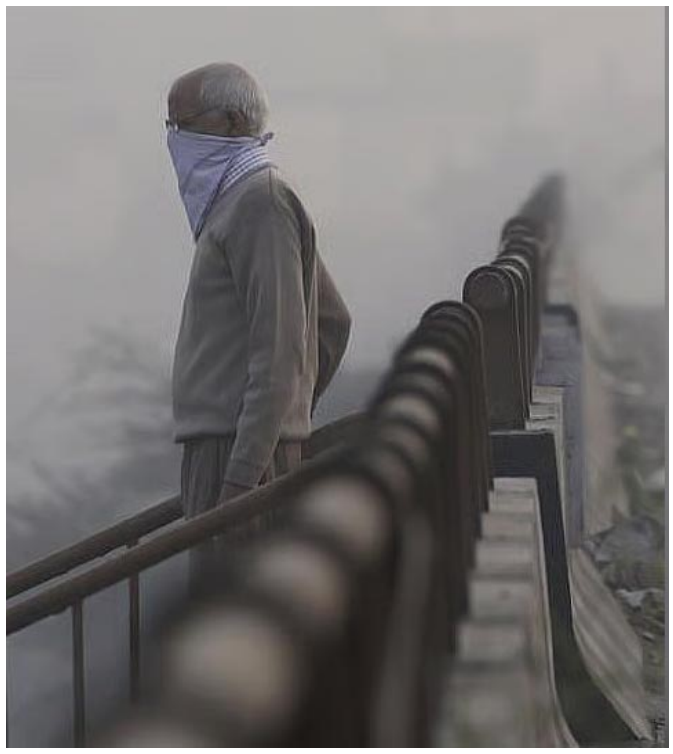

दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण का स्तर खतरनाक स्थिति में पहुंच गया है। गाजियाबाद में एक्यूआई 434 तक पहुंच गया, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन की सुरक्षित सीमा से 860 फीसदी अधिक है।

दिल्ली में भी स्थिति गंभीर है, जहां एक्यूआई 370 दर्ज किया गया है। प्रदूषण के महीन कणों के कारण गाजियाबाद में गैस-चैम्बर जैसी स्थिति बन गई है। 248 शहरों के लिए जारी आंकड़ों के विश्लेषण से पता चला है कि इनमें से जहां महज 12.5 फीसदी शहरों में हवा साफ है। आंकड़ों से पता चला है कि प्रदूषण के मामले में बागपत (403) दूसरे जबकि नोएडा (394) तीसरे स्थान पर है। इसी तरह 380 अंकों के साथ हापुड़ चौथे स्थान पर है। मेरठ-दिल्ली में भी स्थिति कमोबेश ऐसी ही है, जो 374 और 370 अंकों के साथ पांचवें और छठे पायदान पर हैं।

ग्रेटर नोएडा (364) सातवें स्थान पर हैं। इसी तरह दस सबसे प्रदूषित शहरों में मुजफ्फरनगर (345), भिवाड़ी (338) और बुलंदशहर (338) भी शामिल हैं। आज देश के दस सबसे प्रदूषित शहरों में उत्तर प्रदेश के आठ शहर (गाजियाबाद, बागपत, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, हापुड़, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर) शामिल हैं। फरीदाबाद में कल से प्रदूषण में गिरावट आई है, जहां पांच अंकों के सुधार के साथ एक्यूआई घटकर 233 पर पहुंच गया। विश्लेषण से पता चला है कि 22 नवंबर 2025 को एक बार फिर देश में गाजियाबाद की हवा सबसे ज्यादा खराब रही, जब वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी एक्यूआई बढ़कर 434 पर पहुंच गया। गौरतलब है कि 21 नवंबर को गाजियाबाद में एक्यूआई 422 दर्ज किया गया था। मतलब कि वहां कल से प्रदूषण में 12 अंकों का इजाफा हुआ है। इसके साथ ही गाजियाबाद में अभी भी स्थिति 'गंभीर' बनी हुई है और वहां गैस-चैम्बर जैसे हालत हैं। रुझानों में सामने आया है कि गाजियाबाद की हवा में प्रदूषण के महीन कण (पीएम10) पूरी तरह हावी हैं। देखा जाए तो वहां फिजाओं में घुला जहर इतना ज्यादा है कि वो लोगों को बेहद बीमार बना देने के लिए काफी है। गाजियाबाद से स्थिति किस कदर खराब है, इसी बात से समझा जा सकता है कि वहां प्रदूषण का स्तर विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निर्धारित सुरक्षित सीमा से 860 फीसदी अधिक है। दूसरी तरफ देश में शिलांग की हवा सबसे साफ है, जहां वायु गुणवत्ता सूचकांक महज 14 रिकॉर्ड किया गया। ऐसे में यदि देश के सबसे प्रदूषित शहर गाजियाबाद की तुलना शिलांग से करें तो वहां स्थिति 30 गुणा खराब है। राजधानी दिल्ली की बात करें तो कल से प्रदूषण में इजाफा हुआ है। हालांकि दिल्ली में अभी भी वायु गुणवत्ता 'बेहद खराब' है, जहां प्रदूषण का स्तर निर्धारित मानकों से 700 फीसदी अधिक है। गौरतलब है कि 11 नवंबर को दिल्ली में साल का सबसे प्रदूषित शहर दिन दर्ज किया गया था, जब एक्यूआई बढ़कर 428 तक पहुंच गया था।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा 22 नवंबर, 2025 को 248 शहरों के लिए जारी आंकड़ों के विश्लेषण से पता चला है कि इनमें से जहां महज 12.5 फीसदी शहरों में हवा साफ है।

वहीं करीब 20.5 फीसदी में स्थिति संतोषजनक बनी हुई है, जबकि दूसरी तरफ 67 फीसदी शहरों में हालात चिंताजनक हैं। मतलब की देश के ज्यादातर शहरों में आज भी हवा चिंताजनक है। राहत की बात यह है कि कल से देश में साफ हवा वाले शहरों की गिनती में 181 फीसदी से अधिक का इजाफा हुआ है। वहीं संतोषजनक हवा वाले शहरों की गिनती में कल से 25 फीसदी की गिरावट आई है। मध्यम वायु गुणवत्ता वाले शहरों की बात करें तो इन शहरों में कल से करीब 2.9 फीसदी का इजाफा हुआ है। खराब वायु गुणवत्ता वाले शहरों से जुड़े आंकड़ों को देखें तो उनकी गिनती में 10.9 फीसदी की गिरावट आई है। दूसरी तरह देश में बेहद खराब वायु गुणवत्ता वाले शहरों की गिनती में 45 फीसदी से अधिक का इजाफा हुआ है, जोकि चिंता का विषय है। फरीदाबाद में वायु गुणवत्ता सूचकांक 233 रिकॉर्ड किया गया है। आंकड़ों से पता चला है कि प्रदूषण के मामले में बागपत (403) दूसरे जबकि नोएडा (394) तीसरे स्थान पर है। इसी तरह 380 अंकों के साथ हापुड़ चौथे स्थान पर है। मेरठ-दिल्ली में भी स्थिति कमोबेश ऐसी ही है, जो 374 और 370 अंकों के साथ पांचवें और छठे पायदान पर हैं। ग्रेटर नोएडा (364) सातवें स्थान पर हैं। इसी तरह दस सबसे प्रदूषित शहरों में मुजफ्फरनगर (345), भिवाड़ी (338) और बुलंदशहर (338) भी शामिल हैं। गौरतलब है कि आज देश के दस सबसे प्रदूषित शहरों में उत्तर प्रदेश के आठ शहर (गाजियाबाद, बागपत, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, हापुड़, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर) शामिल हैं। विश्लेषण से यह भी पता चला है कि जहां बागपत, नोएडा, हापुड़, ग्रेटर नोएडा, मुजफ्फरनगर, भिवाड़ी, बुलंदशहर, भिवानी, यमुना नगर, जींद, टोंक, सोनीपत, कुरुक्षेत्र, कोटा, रोहतक, करनाल, मंडीदीप, बहादुरगढ़, जयपुर, कैथल, गुरुग्राम, पंचकुला, मानेसर, नंदेसरी, ग्वालियर, बूंदी, भीलवाड़ा, झालावाड़, पिंपरी-चिंचवाड़, हावड़ा, बद्दी, देवास, सिंगरौली, धारूहेड़ा, कोलकाता, फरीदाबाद, जैसलमेर, सागर, डूंगरपुर, कटनी, बारां, सवाई माधोपुर, अंकलेश्वर, भरतपुर, बैरकपुर, जबलपुर, हल्दिया, अंगुल, दौसा, करौली, पुणे, चंडीगढ़, पाली आदि शहरों की हवा में प्रदूषण के महीन कण (पीएम2.5) हावी हैं।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्व. नरेशचंद्र सिंह की जयंती पर दी श्रद्धांजलि

भोपाल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शुक्रवार को म.प्र. विधानसभा भवन पहुंचकर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्व. श्री नरेशचंद्र सिंह की जयंती पर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि श्री नरेशचंद्र सिंह राज गोंड प्रदेश के इतिहास में एकमात्र जनजातीय और मध्यप्रदेश के 6वें मुख्यमंत्री रहे। उनकी कार्य अवधि 13 मार्च 1969 से 25 मार्च 1969 तक कुल 13 दिन रही। उनके मुख्यमंत्री बनने का समय संविद सरकार थी। राजनीतिक अस्थिरता की वजह से उनका कार्यकाल बहुत छोटा रहा। इस अवसर पर विधायक श्री भगवान दास सबनानी, विधानसभा के प्रमुख सचिव सहित जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी उपस्थित थे। पूर्व मुख्यमंत्री श्री नरेशचंद्र सिंह का जन्म 21 नवम्बर 1908 को हुआ था। वे जनजातीय राजवंश के राजा थे। जनवरी 1948 को अपने राज्य के भारत संघ में विलय होने तक वे सारंगढ़ रियासत के शासक थे। आजादी के बाद उन्होंने 1951 में मध्यप्रदेश राज्य विधानसभा के लिए हुए पहले आम चुनाव में जीत हासिल की। वे 1952 से 1969 तक मध्यप्रदेश की विधानसभा (विधायक) के सदस्य और पहले जनजाति कल्याण मंत्री रहे। उन्होंने बिजली और लोक निर्माण विभाग मंत्री का दायित्व भी संभाला था।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक सोनल मेहता केलिए प्रतीक्षा ग्राफिक्स, 127 देवी अहिल्या मार्ग, इंदौर (म.प्र.) से मुद्रित एवं 209-बी शहनाई रेसीडेंसी-2 कनाड़िया रोड इंदौर (म.प्र.) से प्रकाशित। संपादक: डॉ. सोनल मेहता फोन : 0731-2595008 Mail.sonal12mehta@yahoo.co.in 9755040008